



## सम्पादकीय

### लोकतंत्र पर दाग

एक समय था कि जब लोग देश के नेताओं के सार्वजनिक जीवन में आचरण का अनुसरण करते थे। नेताओं को भी समाज में अपनी छवि व परिणाम की फ़िल्म रहती थी। वे कहे को जीते थे। लेकिन हाल के वर्षों में राजनीति में कई क्षयप परिवर्तनों के एसा नेता भी सामने आए हैं जिन्होंने सतामद में चूर होकर तमाम लैकिताओं व मयालाओं को ताक पर रखा। पिछले दिनों कर्नाटक में हासन सीट से जनाव दल (सेक्युलर) के सांसद प्रज्ञल रेवना पर सैकड़ों महिलाओं के साथ दुराचार के जो गंभीर अरोप लगे, उसने राजनीति में पतन की प्रक्रिया को दरार्शा है। आरोपी सांसद का दुस्साहस देखिए कि वह मतदान के दिन तब चुनाव क्षेत्र में रहा और फिर जर्मनी भाग गया। पूर्व प्रधानमंत्री एवंडी देवगौड़ा के गौत्र और पूर्वमंत्री एवंची रेवना के पुत्र प्रज्ञल के बैन उत्तीर्ण व दुराचार दर्शाते करीब तीन हजार वीडियो सार्वजनिक हुए। चुनाव प्रचार के दौरान वीडियो पेन ड्राइव के जरिये बाटे जाते रहे। निसर्दह इस मामले के खुलासे की टाइमिंग के राजनीतिक निहितार्थ है। वहाँ भाजपा के एक नेता ने एक साल पहले भाजपा नेतृत्व को पत्र लिखकर चेताया था कि प्रज्ञल के कुकूलों की पेन ड्राइव कार्रियर के पास पहुंच चुकी है। जिसका उपयोग लोकसभा चुनाव में हथियार के रूप में किया जाएगा। सतामा भाजपा नेतृत्व पर भी है कि हकीकत से वाकिफ होने के बावजूद क्यों प्रज्ञल रेवना को गठबंधन के सहयोगी कोटे से टिकट दिया गया? जब गाय भी कार्रियर की सरकार है तो एक साल पहले जानकारी होने के बावजूद प्रज्ञल रेवना के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? दरअसल, एक सुम्यावशिष्य में एचडी देवगौड़ा परिवार को पकड़ होने की वजह से भाजपा कड़ी कार्रवाई से बचते रहे हैं। बहरहाल, इस सेक्स स्कैंडल के उत्तराधीन और उसके बाद तमाम सफाई के बावजूद जनता दल सेक्युलर और उसकी सहयोगी भाजपा को गहर मिलता रहा। वजह है कि आरोप गंभीर और महिलाओं की अस्मिता से जुड़े हैं निहित रूप से कर्नाटक में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य व सांसदों ने जो कुकूल किये हैं, उसमें भारतीय लोकसभा सीढ़ीदार देश हुआ है। विंडों के देखिये कि जो बड़े राजनेता महिलाओं की प्रशंसा में कर्सी देखते हैं, वे नहीं थहरते हैं, वे नहीं रहते हैं। वे इस शर्मनाक कांड की व्याख्या अपनी सुविधा के अनुसार कर रहे हैं। एक पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार का सांसद अपने में काम करने वाली महिलाओं तक को न बख्ती, इसलिए ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। आरोप है कि प्रज्ञल रेवना ने किसी भी आयु और वर्ष की महिला को नहीं बख्ता है। इतना ही नहीं, सरकारी महिला अधिकारियों कार्मचारियों व पार्टी कार्यकारी तक को हवस का शिकाय बनाने तक के गंभीर आरोप प्रज्ञल पर लगे। वीडियो इसलिये बनाये ताकि शोपांग के बाद लोकलाज के भय से उन्हें चुप रखा जा सके। आरोपों के निशाने पर पूर्व मंत्री व प्रज्ञल के पिता पांडी रेवना भी हैं। हालांकि, प्रज्ञल का आरोप है कि एवाई के जरूरी उसके फैटों से छेड़छाड़ करके वीडियो बनाए गए हैं। लेकिन वह वह निर्देश है तो प्रिय उसे चुके से जर्मनी भागने की वजह पर पड़ी? जिसका सरकारों की मिलियत के काम वह जर्मनी भाग सकता था? वह जह जिवियांस हसी है कि घोर विरोधी राजनीतिक दल व्यावहारिक जीवन में एक दूरों के बड़े नेताओं के बचाने के लिये वक्तव्य का काम करते हैं? सवाल स्वाभाविक है कि जनता दल (एस) ने अलीडी वीडियो मामले में प्रज्ञल को पांटी से निलंबित करने में इतनी देर क्यों की? निसर्दह, ऐसे बैन कुर्तित जनप्रतिनिधि के चुना जाना लोकतंत्र के दाम पर एक दाग सरीखा है। प्रज्ञल के जैसे विकृतिपूर्ण वीडियो सार्वजनिक हुए हैं उसे देखते हुए तकली उच्चसरीय जांच और कार्रवाई की ज़रूरत है। बहरहाल, अब कर्नाटक सरकार द्वारा मामले में एसआईडी के गठन और प्रज्ञल रेवना के खिलाफ बलाकर व अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद उम्मीद जगी है कि दोपी को दीवाने को लीडिंग ऑफिसरों को न्याय मिल सकेगा।



**कमलेश पांडेय**  
वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार  
कहना न होगा कि  
लोकतंत्र, मानवाधिकार,  
मीडिया की स्वतंत्रता  
और भूख्य जैसे मुद्दों पर  
भारत को जानबूझकर  
निशाना बनाया जाता है।  
क्योंकि कुछ सरकारों की आदत  
होती है कि वह दूसरों से जुड़े हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हैं।  
इसलिए भारत सरकार ने भी सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजी से अवगत करा दिया है। इसे दूसरों से जुड़े हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए भारत सरकार ने भी सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजी से अवगत करा दिया है। इसे दूसरों से जुड़े हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए भारत सरकार ने भी सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजी से अवगत करा दिया है। इसे दूसरों से जुड़े हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए भारत सरकार ने भी सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजी से अवगत करा दिया है। इसे दूसरों से जुड़े हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हैं।

भारत सरकार ने अमेरिका की एक प्रतिष्ठित एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) पर भारत में जरी आम चुनाव 2024 की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के आयोग के विपरीत विवरणों में अवधारणा के साथ देखने के साथ आयी है, वैसा कूपी भी दूसरे देश के साथ देखने के नहीं मिला। बावजूद इसके अमेरिका के आयोग की व्याख्या की अद्वितीय देखने की विवरणों में भारत में मानवाधिकार, धार्मिक आजादी, एस की स्वतंत्रता जैसे मुद्दे के जरिये किये जाने वाले हस्तक्षेप भारतीय नेतृत्व वर्द्धित नहीं रह सकता है। इसलिए ऐसे हस्तक्षेप को लेकर सख्ती से जाचाव देने की रणनीति भारत अपना चुका है, जो बहुत बड़ी बात है।

यही वजह है कि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता राष्ट्रीय जायसवाल ने यूएससीआईआरएफ के गठन पर एक दाग सरीखा है। यह देखना अभी बाकी है।

## भारत के विरुद्ध अमेरिकी एजेंसियों समेत पश्चिमी देशों की फिरत पर दमदार पलटवार की है जरूरत, अन्यथा नहीं चेतेंगे

सालाना स्तर पर जारी होने वाली इस रिपोर्ट को राजनीतिक प्रोप्रेंडिंग कहा है। बकूल राणधीर जायसवाल, "यूएससीआईआरएफ को राजनीतिक एजेंडे वाले पक्षपाती संगठनों के रूप में जाना जाता है। इन्हें वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में भारत के बारे में अपना दुश्याचार प्रकाशित करना जारी रखा है। हमें वास्तव में ऐसी उम्मीद भी नहीं है कि वह आयोग भारत की विविधात्पूर्ण, बहुलतावादी और लोकतांत्रिक मूल भावना को समझने की कोशिश भी करेगा। उनके द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए इस ग्राम्यासाधन की सफलता नहीं होगी।"

वूँ तो अमेरिका की चुनाव प्रक्रिया के वैराग वहाँ के राजनीतिक दल और राजनेता कभी चीन तो कभी रूस पर हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने बजाया प्रेस काफ़ेरेस करके अमेरिका की प्रतिष्ठित एजेंसी यूएससीआईआरएफ पर भारत में जारी चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का जो आरोप लगाया है, उसके गहरे निहितार्थ है। वर्तमान अमेरिकी एजेंसी पर लोकतांत्रिक तरीके से होने वाली चुनावी प्रक्रिया में अमेरिकी एजेंसी की तरफ से हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। सभवतावाद यह अमेरिकी एजेंसियों को लेकर भावना के बदले रखैये को भी बतलाता है।

इस बात में कोई दो राय नहीं कि अमेरिका भारत का एक राजनीतिक दल और राजनेता कभी चीन तो कभी रूस पर हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन अब भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने बजाया प्रेस काफ़ेरेस करके अमेरिका की प्रतिष्ठित एजेंसी यूएससीआईआरएफ पर भारत में हस्तक्षेप करने का जो आरोप लगाया है, उसके गहरे निहितार्थ है। वर्तमान अमेरिकी एजेंसी पर लोकतांत्रिक तरीके से होने वाली चुनावी प्रक्रिया में अमेरिकी एजेंसी की तरफ से हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। सभवतावाद यह अमेरिकी एजेंसियों को लेकर भावना के बदले रखैये को भी बतलाता है।

कहना न होगा कि लोकतंत्र, मानवाधिकार, मीडिया की स्वतंत्रता और भूख्य जैसे मुद्दों पर भारत को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है। क्योंकि कुछ सरकारों की आदत होती है कि वह दूसरों से जुड़े हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए भारत सरकार ने भी भारतीय निशाने की विदेश मंत्रालय से आग्रह किया गया है कि भारत को भी धार्मिक आजादी, एस की स्वतंत्रता जैसे मुद्दे के जरिये जाने वाले हस्तक्षेप भारतीय नेतृत्व वर्द्धित नहीं रह सकता है। इसलिए ऐसे हस्तक्षेप को लेकर सख्ती से जाचाव देने की रणनीति भारत अपना चुका है, जो बहुत बड़ी बात है। इस बात को नहीं भुलाया जा सकता कि ये वही पश्चिमी संस्थाएं हैं जो कृषि कानून विरोधी उग्र अदोलन और साहीन बाग के अपाजक धरने को एक तरह से देखती हैं। और खेल अवैध प्रवासियों को पकड़-पकड़ कर रखांडा क्वार्ट रैख्यों पर भेज रहा है? इसी तरह कनाडा में हड़ताली ट्रक ड्राइवरों से निपटने के लिए आपाकाल क्वार्ट रैख्यों पर एक दूसरी बात है। इस बात को नहीं भुलाया जा सकता कि ये वही पश्चिमी संस्थाएं हैं जो जागृत कानून विरोधी उग्र अदोलन और साहीन बाग के अपाजक धरने को एक तरह से देखती हैं। वैसे भी भारत को केवल प्रतिक्रिया ही नहीं देनी चाहिए, बल्कि बाकायदा रिपोर्ट जारी कर बहुत बातों को लेकर खात्री रखनी चाहिए। इस बात को नहीं देखती है कि एस सेंट्रल एक दूसरी बात है। जब भारत अपनी चुनावी देशों से छिपी हुई नहीं है। अमे



